

रजिस्टर्ड नं० एल०-३३-एस० एम० १३-१४/९७



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 21 अगस्त, 1997/30 आवण, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-४, 21 अगस्त, 1997

संख्या 1-53/97-वि०—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रतिया एवं कार्य मंचालन नियमावली,
1973 के नियम 135 के अन्तर्गत “हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997 (1997

का विधेयक संख्यांक 15)" जो आज दिनांक 21 अगस्त, 1997 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरापालित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित कारणे हेतु प्रेसित बिगा जाता है।

भग्य शाहारी,
सचिव ।

1997 का विधेयक संख्या 15.

हिमाचल प्रदेश कूपि-उपज मण्डी (मंजोधन) विधेयक, 1997

(विधान सभा में प्रस्तावित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कूपि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 (1970 का ४) का और
मंजोधन कारने के लिए विधेयक।

मार्ग गणराज्य के अन्तर्भूतिक्षेत्रों वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-
नियत रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का गंकित नाम हिमाचल प्रदेश कूपि-उपज मण्डी (मंजोधन) अधिनियम, 1997 है।

2. हिमाचल प्रदेश कूपि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 की घाग 37 को घाग 37
उप-घाग (2) में "गाउ सरकार" शब्दों के स्थान पर, "मण्डल शासन" शब्द रख का योग्यता
जाएगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 की धारा 37 के अधीन बोर्ड द्वारा पारित आदेशों से व्यक्ति कोई व्यक्ति राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा। राज्य सरकार के भार को कम करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार की अपीली शक्तियां क्षेत्र के मण्डल आयुक्त को प्रदत्त की जानी चाहिए। व्यक्ति पक्षकारों की राज्य सरकार की तुलना में मण्डल आयुक्त के कार्यालय तक आसान पहुंच होगी और अपीलें तीव्र गति से विनिश्चित की जाएंगी। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

सुजान सिंह पठानिया,
प्रभारी मन्त्री।

शिखला :

21 अगस्त, 1997

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 1997.

**THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE
MARKETS (AMENDMENT) BILL, 1997**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969 (Act No. 9 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 1997.
2. In section 37 of Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969, in sub-section (2), for the words "State Government", the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

Short title.

Amend-
ment of
section
37.

9 of 1970.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 37 of the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969, any person aggrieved by the orders passed by the Board can appeal to the State Government whose decision shall be final. In order to lessen the burden of State Government, it has been decided that the appellate powers of the State Government should be conferred upon the Divisional Commissioner of the area. The aggrieved parties will have easy access to the Divisional Commissioner's office in comparison to the State Government and appeals would be decided more speedily. This has necessitated amendment in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

SUJAN SINGH PATHANIA,
Minister-in-charge.

SHIMLA :

The 21st August, 1997.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-